भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 276

बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

276 श्री पी. विल्सन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) संबंधी नीति के निर्माण के पश्चात् देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केंद्र आवंटित किए गए हैं;
- (ख) पीएसीएस द्वारा पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए कितने आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, और तमिलनाडु में कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केंद्र आवंटित किए गए हैं; और
- (ग) क्या मंत्रालय की 'विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना' के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को गोदामों का निर्माण करने में सक्षम बनाया गया है, यदि हां, तो किस प्रकार की अन्य कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है तथा इस पहल से प्राथमिक कृषि ऋण समितियां किस प्रकार सशक्त होंगी तथा इससे तमिलनाडु के किसान किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी है ।

दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ श्री पी. विल्सन, माननीय संसद सदस्य द्वारा “प्राथमिक कृषि ऋण समितियां” के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 276 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) के अंतर्गत पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल डीलरशिप में प्राथमिकता देने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है। खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार PACS ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (PSU OMCs) द्वारा नए खुदरा आउटलेट (RO) डीलरशिप के लिए विज्ञापन जून और जुलाई 2023 में जारी किए गए थे। उक्त विज्ञापनों के तहत, 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 394 PACS (ओपन श्रेणी: 261, CC-2: 133) ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए, जिनमें से 44 PACS (ओपन श्रेणी: 16, CC-2: 28) को OMCs द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी किए गए हैं, और गुजरात राज्य में 2 PACS तथा तेलंगाना राज्य में 1 PACS में RO चालू किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य में, 37 PACS ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, जिनमें से 4 PACS (ओपन श्रेणी) को OMCs द्वारा LOI जारी किए गए हैं।

(ग): जी हां, मान्यवर। देश में विकेंद्रीकृत अन्न भंडार क्षमता सृजित करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को अनुमोदित किया है जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना, कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), इत्यादि जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग सुविधाएं, शीतागार इकाइयां, पैकहाउस, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का सृजन करना है। इन अवसंरचना का उद्देश्य मूल्य संवर्धन का बढ़ावा, भंडारण स्थिति में सुधार और बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कर अंततः किसानों की आय में वृद्धि करना है।

इस योजना की पायलट परियोजना के तहत तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले में सिलामराथुपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में 1,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा, यह उन्नत भंडारण और कृषि अवसंरचना तमिलनाडु सहित देशभर में खाद्यान्न की परिवहन लागत को कम करने और उनकी बर्बादी में कमी लाने तथा किसानों को बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इस योजना का उद्देश्य PACS को उनकी वित्तीय स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने में सक्षम बनाना है, जिससे ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास में योगदान मिल सके।